

## नगर निकाय वित्त रपिर्ट: RBI

### प्रलिमिंस के लयि:

स्थानीय शासन, RBI, नगर नगिम, GDP, GST ।

### मेन्स के लयि:

नगर नगिम वित्त रपिर्ट, RBI ।

## चर्चा में क्यों?

हाल ही में [भारतीय रजिस्टर बैंक \(RBI\)](#) ने सभी राज्यों में 201 [नगर नगिमों \(MCs\)](#) के लयि बजटीय आँकड़ों का संकलन और वशिलेषण करते हुए नगर निकाय नगिम वित्त रपिर्ट जारी की है ।

- RBI की रपिर्ट '[नगर नगिमों के लयि वित्तपोषण के वैकल्पिक स्रोतों](#)' को अपने वषिय के रूप में तलाशती है ।

## नगर नगिम:

### परचिय:

- भारत में नगर नगिम दस लाख से अधिक लोगों की आबादी वाले किसी भी महानगर/शहर के विकास के लयि ज़रिमेदार एक शहरी स्थानीय निकाय है ।
  - महानगर पालिका, नगर पालिका, नगर नगिम, सटी कारपोरेशन आदि इसके कुछ अन्य नाम हैं ।
- राज्यों में [नगर नगिमों](#) की स्थापना राज्य वधिनसभाओं के अधिनियमों द्वारा तथा केंद्रशासति प्रदेशों में संसद के अधिनियमों के माध्यम से की जाती है ।
- नगरपालिका अपने कार्यों के संचालन के लयि [संपत्तिका र राजस्व](#) पर अधिक नरिभर रहती है ।
- भारत में [पहला नगर नगिम वर्ष 1688 में मद्रास](#) में स्थापति कयि गया तथा उसके बाद वर्ष 1726 में [बॉम्बे और कलकत्ता में नगर नगिम](#) स्थापति कयि गए ।

### संवधानकि प्रावधान:

- भारत के संवधिन में [राज्य के नीतनिदिशक सदिधांतों](#) में अनुच्छेद-40 को शामिल करने के अलावा स्थानीय स्वशासन की स्थापना के लयि कोई वशिषिट प्रावधान नहीं कयि गया था ।
- [74वें संशोधन अधिनियम, 1992](#) ने संवधिन में एक नया भाग IX-A सम्मलित कयि है, जो नगर पालिकाओं और नगर पालिकाओं के प्रशासन से संबंधित है ।
- इसमें अनुच्छेद 243P से 243ZG शामिल हैं । इसने संवधिन में एक नई [बारहवीं अनुसूची](#) भी जोड़ी । 12वीं अनुसूची में 18 मद शामिल हैं ।

## नषिकर्ष:

### नगर नगिमों (MCs) का खराब कामकाज:

- भारत में [स्थानीय शासन](#) की संरचना के संस्थागतकरण के बावजूद नगरपालिका के कामकाज में कई खामरिाँ हैं और उनके कामकाज में कोई सराहनीय सुधार नहीं हुआ है ।
- परिणामस्वरूप भारत में शहरी आबादी के लयि आवश्यक सेवाओं की उपलब्धता और गुणवत्ता खराब बनी हुई है ।

### वतितीय स्वायत्तता की कमी:

- अधिकांश नगरपालिकाएँ केवल बजट तैयार करती हैं और बजट योजनाओं के खिलाफ वास्तविक समीक्षा करती हैं, लेकिन बैलेंस शीट और नकदी प्रवाह प्रबंधन के लयि अपने लेखा परीक्षण वतितीय वविरणों का उपयोग नहीं करती हैं, जिसके परिणामस्वरूप महत्त्वपूर्ण अक्षमताएँ

देखी जाती हैं।

- जबकि भारत में नगरपालिका बजट का आकार अन्य देशों के समकक्षों की तुलना में बहुत छोटा है, राजस्व में संपत्तिकर संग्रह और सरकार के ऊपरी स्तरों से करों एवं अनुदानों का अंतरण होता है, जिसके बावजूद वित्तीय स्वायत्तता की कमी बनी रहती है।

#### ■ न्यूनतम पूंजीगत व्यय:

- स्थापना व्यय, प्रशासनिक लागत और ब्याज तथा वित्त शुल्क के रूप में नगरपालिका का प्रतबिद्ध व्यय बढ़ रहा है, लेकिन पूंजीगत व्यय न्यूनतम है।
- नगरपालिका बॉण्ड के लिये एक सुविकसित बाजार के अभाव में नगरपालिकाएँ ज़्यादातर बैंकों और वित्तीय संस्थानों से उधार व केंद्र / राज्य सरकारों से ऋण पर अपने संसाधन अंतराल को पूरा करने के लिये भरोसा करती हैं।

#### ■ स्थिर राजस्व/व्यय:

- भारत में नगरपालिका राजस्व/व्यय एक दशक से अधिक समय से **सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी)** के लगभग 1% पर स्थिर है।
- इसके विपरीत ब्राज़ील में सकल घरेलू उत्पाद का 4% और दक्षिण अफ्रीका में सकल घरेलू उत्पाद का 6% नगरपालिका राजस्व / व्यय है।

#### ■ अप्रभावी राज्य वित्त आयोग:

- सरकारों ने नियमिति और समयबद्ध तरीके से राज्य वित्त आयोगों (एसएफसी) का गठन नहीं किया है, जबकि उन्हें प्रत्येक पाँच वर्ष में स्थापति किया जाना अपेक्षित है। तदनुसार, अधिकांश राज्यों में, एसएफसी स्थानीय सरकारों को नधियों का नियम-आधारित अंतरण सुनिश्चित करने में प्रभावी नहीं रहे हैं।

## सुझाव:

- नगरपालिका को विभिन्न प्राप्त और व्यय मदों की **उचित नगिरानी एवं प्रलेखन के साथ ठोस तथा पारदर्शी लेखांकन प्रथाओं को अपनाने** व अपने संसाधनों को बढ़ाने के लिये विभिन्न प्रगतशील बॉण्ड, भूमि-आधारित वित्तपोषण तंत्र का पता लगाने की आवश्यकता है।
- शहरी जनसंख्या घनत्व में तेज़ी से वृद्धि, हालांकि बेहतर शहरी बुनियादी ढाँचे की मांग करती है, इसलिये स्थानीय सरकारों को वित्तीय संसाधनों के अधिक प्रवाह की आवश्यकता होती है।
- समय के साथ नगर नगिमों की राजस्व सृजन क्षमता में गरिबत के साथ ऊपरी स्तरों से करों और अनुदानों के हस्तांतरण पर निर्भरता बढ़ी है। इसके लिये नवोन्मेषी वित्तपोषण तंत्र की आवश्यकता है।
- भारत में नगर पालिकाओं को कानून द्वारा अपने बजट को संतुलित करने की आवश्यकता है, और किसी भी नगरपालिका उधार को राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित करने की आवश्यकता है।
- नगर नगिम राजस्व उछाल में सुधार लाने के लिये, केंद्र तथा राज्य अपने **GST (वस्तु और सेवा कर)** का छठवाँ हिससा साझा कर सकते हैं।

## UPSC सविलि सेवा परीक्षा वगित वर्ष प्रश्न

प्रश्न. भारत में पहला नगर नगिम नमिनलखिति में से कहाँ स्थापति किया गया था? (2009)

- (a) कलकत्ता
- (b) मद्रास
- (c) बॉम्बे
- (d) दलिली

उत्तर: (B)

**स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस**